निजी चीनी मिलों ने उप्र सरकार को दिया धन्यवाद

वीरेंद्र सिंह रावत
लखनऊ, 13 नवंबर

मिलों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उद्योग की दिक्कतों को देखते हुए व्यावहारिक फैसला लिया

गन्ने का मूल्य पिछले साल के स्तर पर ही बनाए रखने के लिए निजी चीनी मिलों ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को धन्यवाद किया है। निजी चीनी मिलों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने चीन उद्योग ही राह में आ रही विभिन्न बाधाओं को देखते हुए 'व्यावहारिक' रवैया अपनाया है।

पिछले कई महीनों से सरकार और चीनी मिलों के बीच गन्ने की कीमत और मौजूदा पेराई सत्र में मिलों के परिचालन को लेकर गतिरोध बना हुआ था। ऐसे में राज्य सरकार का यह फैसला दोनों पक्षों के बीच खटास कम करेगा।

बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए गन्ना के राज्य समर्थित मूल्य में बढ़ोतरी नहीं करने की घोषणा की थी। गन्ने की तीन विभिन्न किस्मों की प्रभावी कीमत क्रमशः 275, 280 और 290 रुपये प्रति क्विंटल है। 2012-13 में उत्तर प्रदेश ने गन्ने की सामान्य किस्म का राज्य समर्थित मूल्य 17 प्रतिशत बढ़ा दिया था। गन्ने की कुल पैदावार में सामान्य किस्म की बड़ी हिस्सेदारी होती है।

दूसरी तरफ किसान गन्ने की कीमतें बढ़ाकर 350 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे थे। इसके जवाब में चीनी मिलों ने पिछले साल चीनी की कीमतें निचले स्तर पर रहने का हवाला देते हुए कहा कि वे पिछले साल के मूल्य के बराबर भी भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं। मिलों ने कहा कि उन पर गन्ना किसानों की बकाया रकम का बड़ा बोझ है। निजी चीनी मिलों पर 2013-14 का 1,8000 करोड़ रुपये बकाया हैं।

चीनी उद्योग ने राज्य सरकार के फैसले पर अब तक कोई टिप्पणी करने से परहेज किया है। उद्योग ने कहा है कि वह फैसले का चीनी मिलों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर रहा है। उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन के सचिव दीपक गुप्ता ने आज शाम लखनऊ में एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, 'उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग राज्य सरकार के फैसले की सराहना करता है। राज्य सरकार ने चीनी उद्योग की समस्याओं को सुलझाने में सकारात्मक रवैया दिखाया है।'

Business Standard
14/11/14